नोबेल प्राइज़ विजेता युगल डुफलो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

न्यू.ज़ैड.एच. में, डुफ़लो और बनर्जी मिलकर लेमन सेंटर फॉर डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक पॉलिसी का नेतृत्व करेंगे। यह केन्द्र "ब्राज़ील की लेमन फाउंडेशन" की 2.6 करोड़ स्विस फ्रैंक (लगभग 3.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर) की मदद से स्थापित किया जा रहा है। इस केन्द्र का उद्देश्य नीति-उन्मुख अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और विशेष रुप से, स्विट्ज़रलैंड व ब्राज़ील सहित, दुनिया भर के शिक्षाविदों व नीति-निर्माताओं को जोड़ना है।

यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष माइकल शैपमैन ने बताया, "हमें गर्व है कि दुनिया के दो सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वे वैज्ञानिक सिद्धांत को सामाजिक प्रभाव से जोड़ते हैं, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी उपस्थिति हमारे मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय पहचान को मज़बूत करेगी।"

डुफ़लो ने कहा कि नया लेमन सेंटर उन्हें "ऐसा अवसर देगा, जिससे वे अपने उस कार्य को आगे बढ़ा सकें, जो अकादमिक शोध, छात्र मार्गदर्शन और वास्तविक नीति-निर्माण के बीच सेतु का काम करता है।"

बनर्जी ने भी यूज़ैडएच से कहा कि "हमें पूरा विश्वास है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख हमारे लिए शोध और नीति-निर्माण का एक उत्कृष्ट वातावरण प्रदान करेगी।"

हालांकि ये दोनों एमआईटी में पार्ट-टाइम सेवा देंगे और अपना रिसर्च नैटवर्क "अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पीएएल) जारी रखेंगे। एमआईटी, जहां वे लंबे समय से हैं, पहली युनिवर्सिटी है जिसने ट्रंप प्रशासन द्वारा तय की गई नई संघीय फंडिंग शर्तों को खारिज कर दिया है।

एमआईटी की अध्यक्ष सैली कॉर्नब्लथ ने अमेरिकी शिक्षा सचिव लिंडा मैकमैहन को लिखे पत्र में कहा कि वे वाइट हाउस के उस ज्ञापन का समर्थन नहीं कर सकतीं, जो शोध फंडिंग को उन नीतियों से जोड़ता है, जो अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नामांकन, विविधता कार्यक्रमों (डायवर्सिटी मैज़र्स) और लैंगिक परिभाषाओं पर प्रतिबंध लगाती हैं।

वाइट हाउस द्वारा नौ शीर्ष विश्वविद्यालयों को ज्ञापन भेजे गये हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्रमुख हैं, ब्राउन, वर्जीनिया, डार्टमाउथ और वैंडरबिल्ट।

ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से, ट्रंप प्रशासन ने उच्च शिक्षा को रुढ़िवादी शिक्षा मॉडल की ओर मोड़ने, विविधता कार्यक्रमों को सीमित करने और शैक्षिणक स्वायत्तता घटाने के प्रयास किए हैं। नवीनतम संघीय आँकड़ों के अनुसार, अगस्त में अमेरिका आने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या लगभग 20 प्रतिशत घट गई, जब विश्वविद्यालयों का नया शैक्षिणक वर्ष शुरू हुआ था, कुल 3,13,138 छात्र अध्ययन वीज़ा पर अमेरिका पहुंचे, जो 2024 के अगस्त माह की संख्या से कम हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट ट्रंप प्रशासन की कठोर वीज़ा संवीक्षा के कारण है। मई के अंत में विदेश विभाग ने विदेशी छात्रों के वीज़ा साक्षात्कार तीन सप्ताह के लिए रोक दिए थे और बाद में उन्हें सोशल मीडिया जाँच के साथ पुनः शुरू किया। जून में 19 अफ्रीकी, एशियाई और मध्य-पूर्वी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने से स्थिति और अनिश्चित हो गई।

फेडरल डेटा के अनुसार, सबसे बड़ी गिरावट अफ्रीका (33 प्रतिशत), एशिया (24 प्रतिशत, जिसमें भारत से 45 प्रतिशत की गिरावट शामिल है) और मध्य पूर्व (17 प्रतिशत) से आई है।

'सभी बोइंग 787 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ग्राउंड रखा जाए, जब तक व्यापक विद्युत प्रणाली जांच पूरी नहीं हो जाती, एआई-117 और एआई-154 की स्वतंत्र जाँच कराई जाए, और एयर इंडिया की रखरखाव प्रक्रियाओं की डी.जी.सी.ए. द्वारा विशेष ऑडिट की जाए। संघ ने विशेष रूप से "मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट (एम.ई.एल.)" अनुमोदनों और बार-बार आने वाली तकनीकी खराबियों पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा है।

कैप्टन रंधावा ने कहा, "हमारे विमान में सवार यात्री यह भरोसा करते हैं कि वे पूरी तरह सुरक्षित और अच्छी तरह से रखरखाव किए गए विमान में उड़ रहे हैं। एयरलाइन और नियामकों का कर्तव्य है कि इस भरोसे को टूटने न दें। किसी भी तरह का समझौता अस्वीकार्य है।" यह पत्र नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, डी.जी.सी.ए. महानिदेशक और संयुक्त महानिदेशक (एयर सेफ्टी) को भी भेजा गया है, ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके। विमानन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रखरखाव में ढिलाई के ऐसे मामलों के बेहद खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, खासकर लंबी दूरी की उड़ानों में, जहाँ विद्युत प्रणालियों की विश्वसनीयता और बैकअप बेहद जरूरी होते हैं।

पूर्व कॉमर्शियल पायलट और सुरक्षा सलाहकार ने कहा, "संचालन क्षमता कभी भी सुरक्षा से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बोइंग 787 एक अत्याधुनिक विमान है, लेकिन इसकी जटिलता का मतलब यह है कि छोटी-सी रखरखाव की चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है।"

अब एयर इंडिया के सामने एक अहम फैसला है, क्या वह जाँच के बीच उड़ानें जारी रखे या फिर गहन निरीक्षण करवाने के लिए 787 बेड़े को उड़ान भरने से रोकने का एहतियाती कदम उठाए। एफ.आई.पी. के लिए रूख बिल्कुल स्पष्ट है। कैप्टन रंधावा ने लिखा, "हर यात्री और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। विमानों को ग्राउंड करना, रखरखाव की जाँच करना और बार-बार होने वाली खराबियों की जाँच कराना आवश्यक कदम हैं। इससे कुछ भी कम, जिम्मेदारी से चूकना होगा।"

यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित होने के साथ-साथ, इस घटनाक्रम ने भारत में एयरलाइन रखरखाव की जवाबदेही और निगरानी पर नई बहस छेड़ दी है।

एयर इंडिया पर भरोसा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए यह स्थिति एक सच्चाई को उजागर करती है। विमानन क्षेत्र में सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

बड़े पैमाने पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्षेत्रीय दलों या यहाँ तक कि एनडीए खेमे में शामिल हो रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव से पहले दलबदल आम बात है, लेकिन इस बार का पैमाना चिंताजनक है। पटना स्थित एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, "बिहार में निष्ठा बदलना हमेशा से आम रहा है, लेकिन इस बार जिस स्तर पर नेता पार्टी बदल रहे हैं, वह इस बात का संकेत है कि राज्य की बदलती सत्ता-समीकरणों को लेकर नेताओं में गहरी अनिश्चितता है।"

भाजपा और जद (यू) के नेतृत्व वाला एनडीए एक ओर अपने अंदरूनी असंतोष को संभालने में जुटा है और स्थिरता की छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व विवादों और सीटों के बँटवारे पर मतभेदों से जूझ रहा है।

उम्मीदवारों की अंतिम सूची अगले 48 घंटों में जारी होने की संभावना है। दोनों खेमों के प्रमुख नेता और रणनीतिकार दलबदल से उत्पन्न हालात को संभालने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी सूत्रों का मानना है कि अंतिम समय पर हुए ये पलायन कई सीटों पर जातीय समीकरण और स्थानीय गठजोड़ को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे मुकाबला और अधिक अप्रत्याशित हो गया है।

जैसे-जैसे प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ रहा है, एक बात साफ है, बिहार की राजनीति, जो अपनी अस्थिरता के लिए मशहूर है, एक बार फिर उसी पहचान को साबित कर रही है। दलबदल की यह लहर राज्य को हाल के वर्षों के सबसे अनिश्चित चुनावों में से एक की ओर ले जा रही है।

बिहार में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करीब डेढ़ घंटे तक मीटिंग पर नतीजा नही दिया। शाम को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी नड्डा के आवास पर पहुंचे और डेढ़ घंटे तक चली बैठक का भी नतीजा नही निकला।

यूक्रेन युद्ध के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की है कि चीन से अमेरिका आने वाले सभी निर्यातों पर मौजूदा 30 प्रतिशत शुल्क के अलावा 100 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ़ लगाया जा सकता है। इस धमकी ने चीन को झकझोर दिया है, और उसने जवाबी कदमों की तैयारी शुरू कर दी है। धीरे-धीरे और लगभग अनिवार्य रूप से, अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह आर्थिक युद्ध किसी सैन्य टकराव में बदल जाएगा या दोनों देश किसी तरह इसे टाल लेंगे - यही आने वाले समय की सबसे अहम कड़ी होगी।

अपने पुराने बैंक खाते में पैसे जमा करके भूल गए?

जो आपका है उसे वापस दिलाने में आरबीआई आपकी मदद करेगा।

आपके बैंक के निष्क्रिय खाते (2 वर्ष से ज़्यादा और 10 वर्ष तक असक्रिय) में जमा पैसे / दावा न की गई जमा राशि (10 वर्ष से अधिक) को आरबीआई के डीईए फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप या आपके क़ानूनी वारिस उसे कभी भी वापस ले सकते हैं।

आपके पैसे वापस पाने के 3 आसान चरण

1. आपके बैंक की किसी भी शाखा में जाएं, भले ही वो आपकी नियमित शाखा न हो।
2. केवाईसी दस्तावेजों (आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस) के साथ फॉर्म जमा करें।
3. सत्यापन के बाद ब्याज समेत, यदि है तो, अपने पैसे वापस पाएं।

दावा न की गई संपत्ति के संबंध में आयोजित विशेष शिविरों में जाएं, जिसे देशभर के सभी ज़िलों में अक्तूबर से दिसंबर 2025 के बीच लगाए जाएँगे।

आपके दावा न किए गए पैसे के बारे में जानने के लिए

आपके बैंक की वेबसाइट पर खोजें या आरबीआई के UDGAM पोर्टल (https://udgam.rbi.org.in) पर देखें, जिसमें फ़िलहाल 30 बैंक शामिल हैं।

क्यूआर कोड स्कैन कीजिए

अधिक जानकारी के लिए https://rbikehtahai.rbi.org.in देखिए
प्रतिक्रिया के लिए rbikehtahai@rbi.org.in पर लिखिए

आधिकारिक व्हॉट्सऐप नंबर 99990 41935

जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908